नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार 29 जनवरी 2009

क्लाइमेट चेंज और ग्रामीण विकास की चुनौती

मौसम के बदलाव किसानों, मजदूरों और आदिवासियों की जिंदगी और रोजी-रोटी पर असर डाल रहे हैं

भारत डोगरा ॥

इसमें संदेह नहीं है कि ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज हमारी पृथ्वी के लिए बड़ी समस्याएं हैं, पर कोई इस बारे में ज्यादा चिंतित नजर नहीं आता कि ये बदलाव दूरदराज के गांवों में किसानों, मजदूरों व आदिवासियों की जिंदगी, उनकी रोजी-रोटी और टिकाऊ विकास की संभावनाओं पर क्या और कैसा असर डाल रहे हैं। यह चर्चा भी ज्यादा नहीं होती कि इन कारणों से विकट होती आजीविका और पोषण की नई समस्याओं से जूझने के लिए क्या तैयारी हो सकती है और क्या समाधान मिल सकते हैं।

पिछले अरसे में यूपी के बुंदेलखंड इलाके में सूखे का प्रकोप होने की खबरें आई हैं। पता चला है कि करीब पांच वर्षों से वहां मौसम बहुत प्रतिकूल चल रहा है। इस दौरान बुंदेलखंड के सभी 13 जिलों में वर्षा सामान्य औसत से काफी कम रही और विभिन्न महीनों में उसका वितरण भी असामान्य रहा। जिस समय खेतों को बारिश की खास जरूरत थी, उसी समय वर्षा बुंदेलखंड से रूठ गई। लेकिन जब फसल पक कर तैयार खड़ी थी, उस समय वर्षा, आंधी और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी। सिर्फ वर्षा ही नहीं, हाल के वर्षों में मौसम कई महत्वपूर्ण संदर्भों में बदला है।

देखने में आया है कि गेहूं जैसे महत्त्वपूर्ण अनाज की फसल सामान्य से ज्यादा गर्मी होने के कारण अधिक तेजी से परिपक्व होती है। यानी उसका तना तो तेजी से बढ़ जाता है, पर उसमें ठीक से फलियां (टिलर) नहीं निकलतीं, दाने ठीक से नहीं जमते। इस तरह गेहूं का कमजोर उत्पादन होता है। खेतों में कई बार भरपूर हरियाली तो नजर आती है, पर वास्तविक उत्पादन बेहद कम होता है। बुंदेलखंड में कई साल तक तो हालात इतने प्रतिकूल रहे कि बहुत सी धरती बिना बोई ही रह गई।

इसी इलाके में वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक हाल के दौर में महुआ, आंवला, चिरौंजी, तेंदू पत्ते आदि लघु वन उपजों में उल्लेखनीय कमी आई है। अकाल जैसे हालात में पोषण की कमी दूर करने वाले कई कंद-मूल तो अब मिल ही नहीं रहे हैं। महुआ, पलाश जैसे महत्त्वपूर्ण वृक्षों में फूल लगने का समय बदल गया है या फूल बहुत कम नजर आ रहे हैं। चरागाहों व चारे की उपलब्धि पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है, पशुओं की संख्या में कमी आई है और दुग्ध उत्पादन कम हुआ है। मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए पेयजल का संकट बढ़ा है।

मौसम में जिस तरह के बदलाव यहां देखे गए हैं, उनका असर सामान्य सूखे की स्थिति से कहीं अधिक व्यापक व दूरगामी है। कृषि वैज्ञानिकों ने यहां वर्षा, तापमान व नमी (ह्युमिडिटी) सभी में महत्त्वपूर्ण बदलावों के संकेत पाए हैं। इस तेजी से बदलती स्थिति को विश्वव्यापी जलवायु बदलाव के संकट से जोड़ने पर आसानी से समझा जा सकता है।

जाहिर है, जलवायु परिवर्तन के असर बड़े गहरे हैं, इसलिए जरूरी है कि आजीविका की रक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के बीच तालमेल बनाने वाले कार्यक्रम अपनाए जाएं। इस तरह के अनिश्चित मौसम के दौर में किसान ऋणग्रस्त नहीं हों, इसके लिए ऐसी सस्ती तकनीकों से उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिनसे किसानों पर बोझ न पड़े। सरकार से अपेक्षा है कि वह जल व नमी संरक्षण के कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले व पंचायत स्तर पर ऐसे विकास कार्य करवाए।

नमी व जल संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण व हरियाली बढ़ाने, चरागाह सुधारने के प्रयासों को बड़े पैमाने पर और पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। इसके अलावा कई छोटे, पर महत्वपूर्ण उपायों की भी जरूरत है। जैसे, वृक्षारोपण करने से कई महीने पहले से ही उचित स्थान का चुनाव हो जाए, गड्ढे बनाने आदि की तैयारी कर ली जाए। परंपरागत जल-स्रोतों के उचित रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और अच्छे जल-ग्रहण क्षेत्रों में नए तालाब आदि बनाए जाएं।

- बुंदेलखंड में वर्षा कम रही और उसका वितरण भी असामान्य रहा।
- खेतों में हरियाली तो नजर आती है, पर वास्तविक उत्पादन बेहद कम होता है।
- जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती से छोटे किसान अपने बलबूते नहीं निबट सकते।

देखा गया है कि जहां जल व नमी संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का काम अच्छी तरह हुआ है, वहां कृषि व पशुपालन के उचित विकास की बुनियाद तैयार हो जाती है।

जिन कुछ दूसरे उपायों की जरूरत है, उनमें महत्वपूर्ण यह है कि हमारे किसान अपने परंपरागत ज्ञान से ज्यादा सबक लें। सरकार की कोशिश यह है कि वह अधिक जैव-विविधता वाले परंपरागत बीजों को एकत्र करने व किसानों को उन्हें उपलब्ध करवाने के प्रयास तेज करे। गोबर-पत्ती की खाद तैयार करने और नीम जैसे कीटनाशक प्रकृति वाले वृक्षों से फसलों की खतरनाक कीड़ों की रक्षा के साधन हासिल करने चाहिए। जब मौसम की स्थितियां अनुकूल हों, तब रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं के बिना ही अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों का भरपूर उत्पादन हो सकता है। इन उपायों से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी और भूजल के अधिक दोहन की जरूरत नहीं होगी। चारे की बेहतर उपलब्धि से पशुपालन व दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। राहत की बात यह है कि बुंदेलखंड के कुछ इलाकों, जैसे पाठा क्षेत्र में इन्हीं नीतियों पर आधारित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहां चित्रकूट जिले के मानिकफर ब्लॉक की पांच पंचायतों में वॉटर शेड कार्यक्रमों के तहत करीब 5000 हेक्टेयर भूमि के ट्रीटमेंट का कार्य हो रहा है। अभी तक पूरी तरह उपेक्षित रहने वाला आदिवासी युवा आज इन महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन कर रहा है। गांववासियों के सहयोग के कारण चेक डैम आदि बनाने का खर्च कहीं कम आ रहा है।

जहां इस तरह की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है, वहां यह सवाल उठाना भी जरूरी है कि बड़े पैमाने पर चलाई जा रही सरकारी परियोजनाओं के बड़े नतीजे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। सरकार के कृषि, वन, जल संबंधी कार्यों में यह नजर नहीं आता कि किसी ऐसी नई और बहुत बड़ी चुनौती से जूझना है, जिसका सामना पहले नहीं हुआ है। ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती के असर से छोटे किसान अपने बलबूते नहीं निबट सकते। इसलिए सरकार को नीतियों में सुधार करते हुए अनुकूल कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं में पर्याप्त निवेश करना होगा। तभी खेती और किसानी को मौजूदा संकट से उबारा जा सकता है।

(यह लेख सीएसई की जलवायु बदलाव पर फेलोशिप के तहत लिखा गया है)